

मध्य प्रदेश में 'ई-जीरो एफआईआर' व्यवस्था की शुरुआत केवल एक तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि पुलिस व्यवस्था की उस सोच में बदलाव का संकेत है जिसमें पीड़ित को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई जा रही हैं। गवालियर में आयोजित 'अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट' के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया यह पोर्टल साइबर अपराध से जुड़ते आम नागरिकों को बड़ी राहत देने वाला है। आज जब टीके के तरीके बदल रहे हैं, अपराधियों का नेटवर्क राज्य की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला है, ऐसे में थाना-क्षेत्राधिकार की परंपरागत बाधाओं को तोड़ने वाली यह पहल समय की मांग कही जा सकती है। जीरो एफआईआर का विचार पहले भी मौजूद था, पर इसका लाभ सीमित दायरे तक ही पहुंच पाता था। साइबर टीके की शिकायत करने वाले अधिकतर लोग ना केवल थाने से शान्त भटकते थे, बल्कि कई मामलों में दैरी के कारण पैसा वापस करने की संभावना भी खत्म हो जाती थी। ऐसे में 'ई-जीरो एफआईआर' का डिजिटल स्वरूप व्यवस्था में

## डिजिटल सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम

गति और जवाबदेही लाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। मध्य प्रदेश द्वारा इसे व्यावहारिक रूप देकर लागू करना स्वागत योग्य कदम है। विशेष रूप से यह तथ्य उल्लेखनीय है कि 1 लाख रूपए से अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर सिस्टम स्वतः एफआईआर दर्ज कर लेगा। इससे आम मामलों में तुरंत कार्रवाई संभव होगी, जहां हर मिनट की देरी अपराधियों को फायदा पहुंचा देती है। शिकायत दर्ज होते ही डेटा भोपाल के सेंट्रल साइबर पुलिस हब को भेजा जाता और बैंक खातों को फ्रीज करने की तैयारी प्रक्रिया, यह दिखाता है कि सरकार ने केवल पोर्टल ही नहीं बनाया, बल्कि उसके साथ कार्रवाई का समन्वित ढांचा भी खड़ा किया है। यही कारण है कि इस व्यवस्था से लोगों का भरोसा बढ़ने की संभावना है। फिर भी, यह समझना होगा कि किसी भी तकनीक का मूल्य उसकी प्रभावशीलता में

निहित होता है। शिकायत को तीन दिनों में सत्यापित करके रेगुलर एफआईआर में बदलने की प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होनी चाहिए। यदि यहां अनावश्यक औपचारिकताएं बढ़ीं, तो यह पहल भी वही नौकरशाही जकड़न झेल सकती है, जिससे निजात दिलाने के लिए इसे शुरू किया गया है। साइबर थानों को पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित मानव बल और आधुनिक तकनीकी साधन उपलब्ध कराना अब सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि कार्रवाई केवल कामजोरों में दर्ज न हो, बल्कि परिणाममूलक हो। नागरिकों का अनुभव बताता है कि कई बार एफआईआर के बाद भी जांच की रफ्तार धीमी रहती है। यदि ई-जीरो एफआईआर के बाद भी पीड़ित को महीनों तक इंतजार करना पड़े, तो इस नवाचार का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। सरकार और पुलिस तंत्र को

यह सुनिश्चित करना होगा कि हर शिकायत पर समयबद्ध जांच, निरंतर फॉलो-अप और पीड़ित को अपडेट देने की पारदर्शी प्रणाली विकसित हो।

साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी व्यवस्था नहीं, बल्कि जागरूकता का विषय भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'साइबर सुरक्षित भारत' विजन और बीएनएसएस की नई व्यवस्था तभी सफल होगी, जब समाज के अंतिम आयतन तक डिजिटल साक्षरता पहुंचे। बैंकिंग, यूपीआई, फिशिंग कॉल, निवेश धोखाधड़ी जैसे खतरों के प्रति लोगों को सतर्क करना उतना ही जरूरी है, जितना अपराध होने के बाद एफआईआर दर्ज करना। 'ई-जीरो एफआईआर' भरोसे का एक मजबूत कदम है, पर यह शुरुआत भर है। अब लक्ष्य होना चाहिए कि साइबर अपराध न केवल दर्ज हो, बल्कि घटे भी। तकनीक, प्रशिक्षण, कानूनी सख्ती और त्वरित कार्रवाई, इन चार स्तंभों पर यदि यह व्यवस्था मजबूती से खड़ी की गई, तो मध्य प्रदेश डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में एक अनुकरणीय मॉडल बन सकता है।

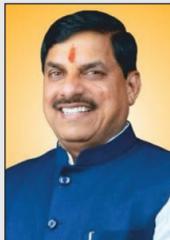
## एमपी ग्रोथ समिट : गवालियर को विकास के नक्शे पर चमकाने की कवायद



हरीश दुबे

पिछड़ गया है जबकि इस शहर से सशक्त राजनीतिक नेतृत्व प्रदेश की सत्ता में प्रभावी है। खुद सिंधिया खेमे के मंत्री 1956 में मंत्र के गठन के दौर की याद करते हुए कहते रहे हैं कि तब प्रदेश के चारों राजभोगी शहरों में विकास से जुड़े हर मामले में गवालियर आगे था लेकिन आज अपने इन प्रतिस्पर्धी शहरों की तुलना में काफी पिछड़ गया है।

अब लगता है कि प्रदेश में दो वर्ष से सत्तारूढ़ मोहन यादव सरकार गवालियर के मामले में गंभीर है और इस ऐतिहासिक शहर का वही सत्तर साल पुराना वैभव लौटाने के उपक्रम में जुटी है। अटलजी की जयंती पर अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट के राज्यस्तरीय आयोजन के लिए गवालियर के चयन से यही जाहिर होता है। समिट के दौरान दो लाख करोड़ की प्रस्तावित एवं प्रगतिशील औद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन, मुकम्मल हो चुके प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, निवेश प्रस्तावों से जुड़े लाभार्थियों का सम्मान तथा रोजगार-केंद्रित पहलों का प्रजेंटेशन तो हुआ ही, उम्मीद बड़ी है कि यह मंच सरकार, उद्योग जगत और युवाओं के मध्य संवाद को सशक्त बनाते हुए गवालियर चंबल में निवेश को गति और रोजगार को



स्थापित भी प्रदान करेगा।

मोहन यादव के सीएम बनने के बाद से गवालियर में दो महत्वपूर्ण बिजनेस कॉन्क्लेव्स हुए हैं, अगस्त 2024 में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और अगस्त 2025 में रीजनल टूरिज्म

सिंधिया को राजा साहब की पदवी ज्योतिरादित्य सिंधिया को तत्कालीन गवालियर रियासत की परंपरा में महाराज की पदवी प्राप्त है। इस पदवी की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भले ही कोई प्रारम्भिकता न हो लेकिन आज एमपी ग्रोथ समिट में अमित शाह ने अपने भाषण के आरंभ में सिंधिया को राजा साहब कहकर भाजपा में उनके कद को और ऊंचा कर दिया, वह भी तब जबकि स्थानीय पार्टी संगठन में उनका नरेंद्र सिंह तोमर से कोल्डवार चल रहा है।

विगत कुछ माह से प्रतिपक्ष के साथ सत्तापक्ष की ओर से भी सार्वजनिक मंचों से खुलकर इस बात पर नाराजगी जताई जाती रही है कि विकास की दौड़ में प्रदेश के अन्य महानगरों की तुलना में गवालियर काफी

### ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी होते ही कांग्रेस में पड़ गई फूट

प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल का दौर चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने दो साल के कार्यकाल के अंतिम दिनों में 780 नए ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी की, जिसका उद्देश्य पार्टी को मजबूत बनाना बताया गया लेकिन सूची जारी होते ही गवालियर चंबल क्षेत्र के तमाम जिलों में असंतोष सामने आया। यहां पार्टी के पुराने गुटों के बीच तनातनी फिर तेज हो गई। जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिव्यजय और कमलनाथ के बीच लंबे समय से गुटबाजी चली आ रही है और ब्लॉक स्तर की नियुक्तियां इस गुटबाजी का नया केंद्र बनी हैं। इसी गुटबाजी का नतीजा है कि ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी होते ही उस वक्त गवालियर में कांग्रेस झटका लगा जब बैरजा मंडल के अध्यक्ष केदार कौशल ने पद लेने से ही इंकार कर दिया। कुछ और विधानसभा क्षेत्रों में भी ऐसे ही हालात बने, जाहिर है कि इससे पार्टी में चिंता है। हालांकि पार्टी के नेताओं ने इस मामले पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन बैरजा ब्लॉक के नए अध्यक्ष द्वारा पद तुकराने से संगठन में अंदरूनी तनाव और अधिक बढ़ने की आशंका है।

### चुनाव से डेढ़ साल पहले प्रभारी मंत्री ने पार्षदों को दी ताकत

गवालियर निगम के चुनाव में अब सिर्फ डेढ़ वर्ष बचा है। साढ़े तीन वर्ष तक अपनी हालत सुधारने में व्यस्त रहे पार्षदों को एकाएक अपने क्षेत्र की चिन्ता गहरा गई है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने भाजपा पार्षद दल की खास बैठक बुलाई तो सत्तारूढ़ दल के पार्षदों को चिंताएं और असंतोष खुलकर सामने आया।

### सिंधिया को राजा साहब की पदवी

ज्योतिरादित्य सिंधिया को तत्कालीन गवालियर रियासत की परंपरा में महाराज की पदवी प्राप्त है। इस पदवी की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भले ही कोई प्रारम्भिकता न हो लेकिन आज एमपी ग्रोथ समिट में अमित शाह ने अपने भाषण के आरंभ में सिंधिया को राजा साहब कहकर भाजपा में उनके कद को और ऊंचा कर दिया, वह भी तब जबकि स्थानीय पार्टी संगठन में उनका नरेंद्र सिंह तोमर से कोल्डवार चल रहा है।

## अमित शाह का संकेत

# मध्यप्रदेश की नई सत्ता-व्यवस्था



कृष्णमोहन झा

भारतीय राजनीति में कई बार सत्तारूढ़ नैर्जायक घटनाएँ भाषणों से नहीं, बल्कि मौन बैठकों और प्रतीकात्मक संकेतों से तय होती हैं। गवालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हालिया दौरा भी इसी श्रेणी में आता है। इसे केवल एक सरकारी कार्यक्रम या विकास केंद्रित आयोजन मानना राजनीतिक दृष्टि से भारी भूल होगा। दरअसल, यह दौरा मध्यप्रदेश की भविष्य की सत्ता-संरचना और नेतृत्व के स्थायित्व पर अंतिम मुहर लगाने वाला साबित हुआ है।

गवालियर के ताज होटल के मराठा सूट में अमित शाह और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के बीच हुई एकांत चर्चा, उसके बाद प्रदेश के अन्य दिग्गज नेताओं से अलग-अलग संवाद, और फिर मंच से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मुक्त कंठ से की गई प्रशंसा—यह पूरा क्रम किसी संयोग का परिणाम नहीं था। यह एक सुनियोजित राजनीतिक पटकथा थी, जिसका उद्देश्य भोपाल की राजनीति को यह स्पष्ट रूप से समझाना था कि अब सत्ता की धुरी, दिशा और निर्णय केंद्र कहां स्थित है।

राजनीति में सबसे बड़ा जोखिम अस्पष्टता होती है। गवालियर में अमित शाह ने उसी अस्पष्टता को समाप्त किया है। अब यह साफ है कि आने वाले समय में मध्यप्रदेश की राजनीति एक नेतृत्व, एक निर्णय केंद्र और एक दिशा के सिद्धांत पर आगे बढ़ेगी। दिल्ली ने अपना संदेश दे दिया है। अब भोपाल की राजनीति की परीक्षा है। सवाल अब 'कौन मुख्यमंत्री है' का नहीं, बल्कि 'कौन इस नेतृत्व के साथ कैसे खड़ा होता है' का है। राजनीति में जो संकेत समय पर पढ़ लेता है, वही भविष्य का हिस्सा बनाता है। बाकी—सत्ता की कहानी में केवल सदर्भ बनकर रह जाते हैं।

कैलाश विजयवर्गीय केवल एक वरिष्ठ नेता नहीं हैं, बल्कि वे भाजपा के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने संगठन और सरकार—दोनों में शक्ति संतुलन के कई दौर देखे हैं। अमित शाह के साथ उनकी एकांत बैठक को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि पार्टी नेतृत्व अब पुराने अनुभव और नए नेतृत्व के बीच किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति को समाप्त करना चाहता है। इसके बाद मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव की जिस तरह प्रशंसा की गई, वह केवल उनके कार्यों की सराहना नहीं थी। वह उन सभी राजनीतिक अटकलों पर विराम था, जो यह मानकर चल रही थीं कि नेतृत्व का केंद्र कहीं और से चलाइए जा सकता है। दिल्ली ने यह साफ कर दिया कि मध्यप्रदेश में अब सत्ता का एक ही चेहरा है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।

अमित शाह की शैली को समझने वाले जानते हैं कि वे सार्वजनिक मंच से बिना

कारण किसी की तारीफ नहीं करते। उनकी हर प्रशंसा के भीतर संगठनात्मक अनुशासन का संदेश छिपा होता है। गवालियर से दिया गया यह संदेश केवल मुख्यमंत्री के समर्थन का नहीं था, बल्कि पार्टी के भीतर मौजूद सभी संभावित शक्ति-केंद्रों के लिए भी था। यह संकेत था कि अब समानांतर राजनीति, अलग-अलग गुटों की सक्रियता या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए सीमित स्थान है। हाईकमान चाहता है कि प्रदेश में राजनीति समन्वय, स्पष्ट नेतृत्व और अनुशासन के सिद्धांत पर आगे बढ़े।

राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को अब 'फ्री हैंड' मिलने जा रहा है। लेकिन इसका अर्थ केवल प्रशासनिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। राजनीति में फ्री हैंड का मतलब होता है— निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता, और उन निर्णयों की पूरी जवाबदेही।

यह वही भरोसा है, जो केंद्रीय नेतृत्व

केवल तब देता है, जब उसे लगता है कि नेतृत्व प्रयोग नहीं, बल्कि दीर्घकालिक निवेश\* है। अमित शाह का खुला समर्थन इस बात का संकेत है कि पार्टी अब मध्यप्रदेश में अस्थिरता या प्रयोग की राजनीति से आगे बढ़कर स्थायित्व चाहती है। अब सवाल यह नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है—यह तय हो चुका है। असली सवाल यह है कि भविष्य के सत्ता-समीकरण कैसे आकार लेंगे।

पहला, संगठन और सरकार के बीच संतुलन अब स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री के पक्ष में झुका हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब यह नहीं कि संगठन कमजोर होगा, बल्कि यह कि संगठनात्मक निर्णय और सरकारी निर्णय एक ही दिशा में चलेंगे।

दूसरा, वे नेता जो अब तक अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर असमंजस में थे, उन्हें यह संदेश मिल चुका है कि आगे बढ़ने का रास्ता मुख्यमंत्री के साथ समन्वय से होकर ही जाता है। अलग-थलग चलने को राजनीति अब लाभकारी नहीं रहेगी।

तीसरा, मंत्रिमंडल और प्रशासनिक संरचना में भी आने वाले समय में ऐसे संकेत दिख सकते हैं, जो यह दर्शाएँ कि मुख्यमंत्री को नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों में अधिक स्वतंत्रता दी जा रही है। यह बदलाव धीरे-धीरे लेकिन स्थायी होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनैतिक विश्लेषक हैं)

## रेगिस्तान बढ़ने से रोक रहा अरावली

विगत 30 वर्षों से अर्धे खनन से अरावली पहाड़ियों को खतरा का मामला उठता रहा है। यह अछूत हुआ कि केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्रालय ने दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली रेंज में नई खनन लीज देने पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया। यह भी निर्देश दिया गया कि जो खदानें पहले से चल रही हैं उन्हें पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अरावली पर्वत श्रृंखला को माइनिंग द्वारा नष्ट करने के खिलाफ राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में प्रदर्शन होते रहे हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्व करारा था जिसमें कहा गया था कि अरावली

अपनी एक चौथाई पहाड़ियां खो चुका है। यदि अरावली नष्ट हो गया तो रेगिस्तान बढ़कर गंगा-यमुना के कछार तक आ जाएगा और दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण चरम पर पहुंचेगा। 1996 के एमसी मेहता मामले में दिए गए फैसले के अनुसार जनता को प्रकृति के विनाश से संरक्षण मिलना चाहिए। गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ियों की वैज्ञानिक परिभाषा सुनिश्चित करने के लिए समिति गठित करने का केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश

दिया था। समिति ने अक्टूबर में रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि 100 मीटर या उससे ऊंचाई के टीलों को पर्वत का हिस्सा माना जा सकता है। इस परिभाषा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और प्रदर्शन होने लगे। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने वन मंत्रालय को बताया कि 100 मीटर ऊंचाई का पैमाना लागू किया तो अरावली की 20 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची 12,081 पहाड़ियां खतरों में आ जाएंगी। यह पहाड़ियां अरावली का 91.3 प्रतिशत हिस्सा हैं और राजस्थान के 15 जिलों में फैली हैं। विशेषज्ञ एजेंसियों ने अरावली के विनाश पर गहरी चिंता जताई है।

अनियंत्रित माइनिंग से पहाड़ियां गायब की जा रही हैं। पर्यावरणविदों तथा जनता की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरिस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन से अरावली के उम्र क्षेत्रों की पहचान करने को कहा है जहां माइनिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए। विस्थापितों के पुनर्वास के उपाय बताने को भी कहा गया है।

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

**CROSS WORD 12123** - डॉ. सागर खादीवाला

1	2	3	4	5	6	
7	8	9				
		10				
11	12	13		14	15	16
17				18		
			19	20		
21	22		23		24	25
26			27			28

पंक्तियों के मध्य का पतला एवं संकरा मार्ग 24. क्षुधा, खाने की इच्छा 26. आक्रमण, चढ़ाई, दौड़ 27. होंठ (उर्दू) 28. निशा, रजनी ऊपर से नीचे

1. बिजली की कड़क, बिजली 2. बड़ी थाली 3. चंचल, स्थिर न रहने वाला 4. झिड़की 5. सजावट, सुंदरता, कांति 6. ध्वनि, गुंजार, आवाज 11. संसार 12. ग्रहण करने या पकड़ने की क्रिया या भाव 13. सब्ज, घास या पत्तियों के रंग का 14. तैसा, वैसा 15. पानी रखने का बड़ा बर्तन (अं.) 16. जगह, भूमि 19. विश्व 20. सूली, ईसा मसीह को सूली देने की टिकट 21. दो समान भागों में से एक, अर्ध 22. युवक, जवान 24. मिट्टी

श म ता क झी क  
नी च य न ध र  
सु म न सु नी ति  
च र क स ता य  
ह ना र द बु  
क मी म न मो ह न  
ना ता य ण ची र ना

बाएँ से दाएँ

1. कथा, प्रशंसा 3. अस्थिर, चंचल, चलायमान, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता हो 5. कोलाहल, जोर की आवाज 7. पानी, जन्मकुंडली में चौथा स्थान 8. पत्र आदि पर लिखा किसी का नाम और रहने की जगह 9. किसी बिक्री की वस्तु का मूल्य, दर 10. एक सी वस्तुओं की माला 11. स्थान 14. निरपेक्ष, परस्पर विरोधी पक्षों से अलग रहने वाला 17. जिसकी (पानी) थाह बहुत नीचे हो, जिसका विस्तार नीचे की ओर अधिक हो 18. बलवान, जिसके साथ सेना हो 19. समीप, निकट 21. वय, उम्र 23. घरों की दो

## ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

**आज जिनका जन्मदिन है**

वर्ष के प्रारंभ में कार्यों की शुरुआत होगी, भूमि भवन आदि का सुख प्राप्त मिलेगा, वर्ष के मध्य में नई योजनाओं पर विचार विमर्श होगा, अधिकारियों के सहयोग से समाज में प्रभाव बना रहेगा, वर्ष के अन्त में आर्थिक कमी के कारण योजनायें वाधित होंगी, शिक्षा में अचानक व्यवधान आयेगा, आकस्मिक यात्रा में व्यय होगा।

मेघ और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को भूमि भवन आदि की प्राप्ति होगी,

वृष और तुला राशि के व्यक्तियों की नई योजना पर विचार विमर्श होगा, कर्क और सिंह राशि के व्यक्तियों को कार्यों में व्यवधान आ सकता है, मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को संयम से काम लेना हितकर रहेगा, मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों की आर्थिक उन्नति होगी, धनु और मीन राशि के व्यक्तियों को निजी कार्यों की रूपरेखा बनेगी।

**मेघ** - विवादास्पद मामलों से अभी आप दूर रहें, रोगी के कार्यों में खर्च होगा, किसी उत्सव में जाने का अवसर मिलेगा, मांगलिक कार्यों पर विचार होगा।

**वृषभ** - आप किसी के साथ मिलकर नई साझेदारी कर सकते हैं। कामकाज पूरा होगा, कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, व्यवसाय लाभप्रद रहेगा।

**मिथुन** - दूसरों की पूंजी का उपयोग कर आप अच्छे लाभ कमा सकते हैं, धन के स्रोत बढ़ेंगे, कुटुंबियों से सुख प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा।

**कर्क** - परिवार में समझौते करके चलना लाभकारी रहेगा, घरेलू यात्रा का योग है, अनावश्यक कार्यों में समय खर्च होगा, दीक्षूप करना पड़ेगी।

**सिंह** - करीबी रिश्तेदारों की चिन्ता होगी, शुभ कार्यों की शुरुआत संभव है, निजी पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, व्यापार व्यवसाय लाभप्रद रहेगा, उन्नति होगी।

**कन्या** - मित्र या रिश्तेदार को मदद करना होगा, राजकीय कार्यों में सफलता मिलेगी, नौकरी में लाभ होगा, मनोरंजक स्थल की सैर होगी।

**तुला** - पौतिक संपत्ति संबंधी विवाद सामने आ सकते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें, कोई समस्या दूर होगी, व्यापार व्यवसाय लाभप्रद रहेगा।

**वृश्चिक** - महत्वपूर्ण कार्य अटक सकते हैं, सावधानी रखकर कार्य करें, समय का सदुपयोग करें, किसी तरह की चोट मोच से शारीरिक कष्ट हो सकता है।

**धनु** - घर की साज सज्जा नवीनीकरण का मन बनेगा, उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा, पारिवारिक चिन्ता रह सकती है, कार्यों में प्राप्ति होगी।

**मकर** - आप योजनाओं को समय से पहले पूरा कर सकते हैं, जिससे अच्छे लाभ होगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, व्यर्थ की चिन्ता रह सकती है।

**कुम्भ** - कार्यक्षेत्र में सफलता के लिये नई तकनीक सीख सकते हैं, लेखनादि के कार्यों में सफलता मिलेगी, संतान प्राप्ति एवं सुख प्राप्ति का योग है।

**मीन** - नये कारोबार का मन बन सकता है, वाहनादि का सुख प्राप्त होगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, खर्च की अधिकता रहेगी।

**उदयकालीन ग्रह चाल**

9	8	के.7 सू. चं. यु.	6	5
	10			
11	12	1	2	3

**पंचांग**

रा.मि. 06 संवत् 2082 पौष शुक्ल सप्तमी शनिवासरे दिन 8/53, उत्तराभाद्रपद नक्षत्रे रात 4/57, व्यतिपात योगे दिन 9/41, वणिज करणे सू.उ. 6/47, सू.अ. 5/13, चन्द्रचार मीन, शु.रा. 12, 2, 3, 6, 7, 10 अ.रा. 1, 4, 5, 8, 9, 11 शुभांक- 5, 7, 1.

**व्यापार भविष्य**

पौष शुक्ल सप्तमी को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से गेहूँ, जौ, चना, बाजरा के भाव में जोरदार तेजी होगी, गुड़ खांड, में नरमि का रूख रहेगा, बादाम कान्या, के भाव में सत्ता रहेगी. भाग्यांक 1415 है।

**SUDOKU 7255**

		5		3				
2			9	5				
9					6			
			9				3	5
6							7	
4	8			1				
			2	4			9	
		8				2		

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें। पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते। पहली का केवल एक ही हल है।

**नवभारत सु-दोड़ 7254**

2	7	6	4	9	5	8	1	3
5	8	1	7	2	3	9	6	4
9	3	4	8	1	6	2	5	7
6	5	9	2	4	8	3	7	1
8	4	7	9	3	1	6	2	5
1	2	3	5	6	7	4	9	8
3	6	5	1	8	2	7	4	9
7	9	2	3	5	4	1	8	6
4	1	8	6	7	9	5	3	2